



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

१८/३/८९

सं. 110]

तई विल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 1989/फाल्गुन 12, 1910

No. 110]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 1989/PHALGUNA 12, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकासन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक वार्षिक विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
आरंभण
मई विल्ली, 3 मार्च, 1989

का आ 173(अ) — बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
(1949 का 10) की धारा 56 क्षण्ड (पद्ध) के साथ पठित धारा 15
की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त गतियों का प्रयोग करने तृप्त, केन्द्रीय
मरम्भार उन धारा 45 की उपधारा (1) के अतिरिक्त भारतीय गिरजे
बैंक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर विचार करने के बाद वर्तकगत
माजिवडे नगरी महकारी बैंक नि, ठाणे (जिसे इसके पश्चात् “महकारी
बैंक” कहा गया है) के सबवर में एकद्वारा 3 मार्च 1989 को बैंक का
कारोबार बदल होने से लेकर, 2 मित्तम्बर 1989 तक और उमं दिन का
मिलाकर अधिस्थगन आदेश जारी करता है जिसके अनुसार अधिस्थगन
आदेश की अवधि के दौरान महकारी बैंक के विरुद्ध गमी कारुशाइयों का
पूर्ण किया जाता अथवा गमी की गमी कार्डाडों को जारी रखना स्वीकृत
किया जाता है किन्तु उन्हें यह है कि इस प्रहार के अधिस्थगन का किसी भी
प्रकार ने भारताद्वारा जो आवागमनी आविस्तरण 1960 के अन्ति

महाराष्ट्र मरम्भार द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उमं अधिकारी पर
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

2 केन्द्रीय मरम्भार एकद्वारा यह निर्देश दती कि स्वीकृत अधिस्थगन
की अवधि के दौरान यह महकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की नियमित
पूर्वानुसन्धान की विना कोई क्षण अथवा अधिम नहीं देगा, किसी अधिम का
नवोकरण नहीं करेगा, बैंक की किसी परिम्परानि का अन्य गतामण अथवा
निपातन नहीं करेगा, किसी प्रकार का इतिहास स्वीकार नहीं करेगा, कोई
निवेदा नहीं करेगा अथवा अन्य दायित्वा प्रांग दनदारियों के मध्य में अथवा
अन्यथा किसी प्रकार की अवायणी नहीं करेगा अथवा अदायगी करना
स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का गमसीता अथवा ठहराव
नहीं करेगा किन्तु बहु निम्नलिखित नीतें गे और निम्नलिखित बीमा नक
प्रथास्थिति अदायगिया अथवा अथवा करेगा —

(1) प्रथेक बचत बैंक अपयग चार आरा अथवा किसी भी नक्षे से
पुकार जाने वाले किसी अन्य जमा खाने में जोप रकम में से 50 रुपये
तक —

वर्णन गि अदा का गमी रकम की दृत गामा दिवा 14.63 अर्द्ध (विस्ता
अन्य वर्षीन कमाव सम्बन्ध खाने में नहा) रु नाम स खाने म जमा तुल
गणि 50 रुपये न ज्यादा न हो।

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अवा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार महकार्ग बैंक का कर्तव्य हो,

(२) ऐसे किसी बैंक द्वापर्यां ने आंतर अथवा लेवा की गणि जो महकार्ग बैंक द्वारा उम तारीख का जारी कर दिये गये हैं जिनका उम तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है तिनको अधिकार आदेश लाग दाता है

(३) ३ मार्च १९४९ को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुए जो भुगतान जाहे वे उम तारीख से पहले, उम तारीख को या उम तारीख के बाद वसूल की गयी हों।

(४) ऐसा कोई व्यय जो किसी महकारी बैंक के द्वारा उमके अथवा उमके विरुद्ध दावर किए गए मुकदम, अपील अथवा महकारी बैंक द्वारा या उमके विकड़ लों गयों दिये या बैंक का मित्रों वालों किसी रकम का बगूर करने के नवय में कर्ता अवश्यक है बगरै कि प्रत्येक मुकदम, अपील अथवा विकड़ के नवय में किए जाने वाले व्यय की रकम ५०० रुपये प्रतिक्रिया हो तो बगरै नवय में किए जाने वाले विकड़ बैंक की लिखित अनुमति ली जाएगी।

(५) ऐसा कोई व्यय जो निवेद बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी का देश प्रोमियत की गणि हो, और

(६) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहा नक कि वह व्यय महकारी बैंक के विकार में बैंक का ईनिक प्रणाली चलान के लिए वरना अनिवार्य हो।

व्यापके कि जहा किसा एक कैलेण्डर मास में किसी मद पर किया गया कुल खने अधिकार अवधि से पहले के द्वारा कैलेण्डर महीनों में उम मद पर किए गए औपन मासिक व्यय में वह जाना हो अथवा उम अवधि के दौरान जहा उम मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उम प्रवार किया जाने वाला अवय २५० रुपये में बहु जाए तो उम प्रकार वा व्यय करने स पूर्व मार्गीय रिजिव बैंक की लिखित रूप में अनुमति नी जाएगी।

३ कर्तव्य गरकार एवं द्वारा यह भी निर्देश देता है कि महकारी बैंक की स्वीकृत अधिकार अवधिकार के विकार के दौरान —

(क) यह महकारी बैंक निम्नलिखित और अदायगिया कर गकेगा अर्थात् महकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विकार महागढ़ सरकार अथवा महागढ़ स्टेट का-प्रापरेटिव एपेक्षा बैंक ति या ठाणे इंडिस्ट्री सेंटर का ग्रामी बैंक ति, ठाणे अथवा मार्गीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी महायक बैंकों या किसी अन्य एक द्वारा महकारी बैंक का किए गए अवयापियां, जो अधिकार अवधिकार के प्रभावी शोल की तारीख ना चुकाए जाने योग न, वी वापरी अदायगिया के लिए आवश्यक हो।

(ख) महकारी बैंक को पूर्वांकन अदायगिया करने के लिए महागढ़ स्टेट का-प्रापरेटिव एपेक्षा बैंक ति अथवा किसी अन्य बैंक को इस संबंध में अपन आपको प्राप्तवाल करना होगा कि इस आदेश द्वारा भवार्ड गयी रैसी का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) यह महकारी बैंक उन ३ दिनों को, जो वसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर औटा मकेगा यदि इस महकारी बैंक को उन ३ दिनों पर कोई अधिकार अथवा हक न हो अथवा दूसी दृश्यो में उसका कोई हित न हो।

(घ) महकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियों का जो इस (बैंक) के पास किसी अवृद्धि, नकद, कज़ा अथवा श्रीवरद्वापर के विकारे गिरवी, दृष्टि बद्धक अथवा अधिक स्त्री गयी हों, अथवा अन्यथा प्रभावित की गयी हों, निम्नलिखित मामला में छोड़कर अथवा दे सकेगा —

(१) किसी ऐसे मामले में जहा अथवा अधिकतावां में मिलने वाली सारी रकम महकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गयी है, और

(२) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक रकम जितनी आवश्यक अथवा सभव हो, निर्दिष्ट अनुपातों से नीचे, जो अधिकार आदेश के प्रभावी होने से पहल लाग थी, इनमें जो भी ऊंच हो, उम माल और प्रतिभूतियों पर मार्जिन के अनुपातों को कम किये विना।

[स. ६-१/८९- एसी]
पी. क नश्यान, अवर मन्त्री

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 3rd March, 1989

S.O. 173(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45, read with clause (2b) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Vartaknagar-Majiwade Nagari Sahakari Bank Ltd., Thane (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 3rd March, 1989 upto and inclusive of the 2nd September, 1989 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance, alienate or dispose of any assets of the bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account, by whatever name called, a sum not exceeding Rs. 50 :

Provided that the total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the

name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 50 :

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before 3rd March, 1989 whether realized before, on or after that date,
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or decrees obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realizing any amounts due to it :

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

- (v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and
- (vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co-operative Bank;

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that, during the period of the moratorium granted to the Co-operative Bank—

- (a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying

loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Thane District Central Co-operative Bank Ltd.; or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

- (b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid :

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

- (c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;

- (d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be has been received by the Co-operative Bank, unconditionally, and

- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportion of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 6—1/89-AC]

P. K. TEJYAN, Under Secy.

